International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(IV), April - June, 2021, pp.185-188

कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. कैलाश चन्द मीना*

प्रस्तावना

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी कोविड–19 से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। आमजन एवं व्यापारियों पर इस महामारी का गहरा असर हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से बाजार मे अस्थिरता हो गयी। उत्पाद एवं सेवाओं की माँग एवं पूर्ति में असंतुलन हो गया। बेरोजगारी में तीव्र बढत हो गयी। आपूर्ति में श्रृंखलाओं पर तनाव, सरकारी आय में कमी, पर्यटन उद्योग का पतन, विदेशी विनिमय अर्जन में कमी, आयात–निर्यात में व्यापक स्तर पर असंतुलन सामन आया है। कोविड–19 के दौरान भारत में अभूतपूर्व आर्थिक व्यवधान के कारण करोड़ो भारतीयों को रोजगार में विमुख होना पड़ा। एक सर्वे के अनुसार 84 प्रतिशत परिवार को इस महामारी से आर्थिक आमदनी से नुकसान उठाना पड़ा है। 32 करोड़ विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिनमें 84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है और 70 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में अध्ययन के लिए आते है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 31 प्रतिशत रह गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की दर से सिकुड़ने की संभावना है। कोविड–19 के दौरान 35 प्रतिशत वृद्धि भारत के अरबपतियों की सम्पत्तियों में हुई है। यह 2009 के 422.9 अरब डालर के आकड़े 70 प्रतिशत अधिक है।

अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार जिस गति से कोविड–19 से विकासशील देशों को आर्थिक झटका लगा है, वह काफी ड्रामेटिक है।

नवीनतम संयुक्त शब्द व्यापार रिपोर्ट के अनुसार–भारत और चीन के अपवाद के साथ विश्व अर्थव्यस्था कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदी मे चली गयी जाएगी। महामारी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से असमानता को बढाया है। चाहे वह असंगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, रिटेल व्यवसाय, ऑटोमोबाइल उद्योग, शेयर बाजार, खेल जगत, शिक्षा, सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियाँ सभी पर विपरित प्रभाव पड़ा है।

कोविड का भारत की अर्थव्यस्था पर प्रहार

भारत एक विशाल देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। भारतीय अर्थव्यस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की विशाल एवं विधिक रूपी अर्थव्यवस्था में देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है, जो मूलभूत सुविधाओं के उपयोग से भी वंचित है। यहाँ कम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रधानता, जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि, निम्न जीवन स्तर पूँजी का अभाव एवं पूँजी निर्माण की धीमी गति, बेरोजगारी व अल्प रोजगार, धन एवं सम्पत्ति में असमानताऐं, तकनीकी ज्ञान का अभाव परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव, असंतुलित विदेशी व्यापार एवं विदेशी अर्जन, असंतुलित औद्योगिक विकास, इत्यादि विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताऐं पायी जाती है।

पिछले वर्ष के आर्थिक घटनाक्रम पर बात करें तों उस पर कोविड–19 की छाप निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यस्था के साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार हुआ है। कोविड–19 संकट के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दो दशक के सबसे बुरे दौर से गुजरी। बाजारों में उत्पाद एवं सेवाओं की खपत कम हो गयी।

---

6 सहायक आचार्य–व्यवसायिक प्रशासन, स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

भारत देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाए और इससे फ्री–मूवमेंट पर पाबंदी लग गई। इसका सबसे बड़ा असर सेवा क्षेत्र पर पड़ा इसने बेरोजगारी बढाई है क्योंकि लोक सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र तक यात्रा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा में भारत में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र मे काम करता है, लॉकडाउन की वजह से काम की कमी ने प्रवासी मजदूरों को अपने गॉव–शहर यानी गृहनगर लौटने को मजबूर कर दिया। पर्यटन रिटेल और आतिथ्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अच्छी बात यह रही कि कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के कारण कम्पनियों को अपने कार्यों का संचालन घर से काम (Work from home) और कही से भी काम करने (Work from any where) के तरीके विकसित किये। जिससे सोशल ड़िस्टेशिंग क मानदण्ड़ में बदलाव हुआ। यह कोविड–19 से पहले अकल्पनीय था, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए शारीरिक रूप से रिर्पोट करना पड़ता था। यह संगठनों आदि कर्मचारियों, दोनों के लिए पॉजिटिक रहा। इससे कम्पनियों को अपने फिक्स ओवर हैड़ को कम करने की अनुमति दी है।

आयात में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत ही अधिक बड़ गयी, शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, उनमें से अधिकांश उत्पादों में चीन की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहती है। भारत का कुल इलैक्ट्रॉनिक आयात लगभग 45 प्रतिशत चीन पर निर्भर करता है। लगभग 65 से 70 प्रतिशत सक्रिय फर्मास्यूरिकल सामग्री और लगभग 90 प्रतिशत मोबाइल फोन चीन से ही भारत आते है।

भारत की लगभग 72 प्रतिशत कम्पनियॉ चीन एवं अन्य देशों में औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण सेवाऐं, आई टी और बीपीओं, लॉजिन्टिकल रसायन, एयरलाइंस और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2021 मं जीडीपी वृद्धि दर में 1प्रतिशत की कमी आ सकती है। वैश्विक बंद के कारण निर्यातों में भारी गिरावट, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। कोविड–19 ने निर्यात, जिसे अर्थव्यवस्था का इंजन माना जाता है, को रोक दिया। वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गयीं, विनिवेश, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रूक गया।

बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था नामिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। पिछले 45 वर्ष में बेरोजगारी सबसे अधिक थी। ग्रामीण मांग पिछले 40 वर्षों में सबसे कम थी।कृषि वृद्धि दर अपने एक दशक के न्यूनतम पर थी इस क्षेत्र में आय के साधन स्थिर हो गये थे। वित्तिय फ्रॉड़ बीते वर्ष में 2 लाख करोड़ हो चुका था। कोविड–19 ऐसी घटना रही जिसमें मानव जाति, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों एवं रीति रिवाजों, परम्पराओं, आर्थिक,राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जितनी भारी तबाही स्वास्थ्य के क्षेत्र में रही उससे कही अधिक तबाही आर्थिक क्षेत्र में रही। बाजार में उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास घट गया। आरबीआई का एनपीए 10 लाख करोड़ के आंकडों का छू रहा था। कोविड–19 के दौरान लगाए गए लॉक डाउन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देश की जीडीपी की वृद्धि दर लगातार गिरना प्रारम्भ हो गयी। सबसे अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्रों में गये और सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र बंद हुए। इसलिए यह वर्ष असंगठित क्षेत्रों के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का भयवाह दौर रहा है।

दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मांग और पूर्ति के दोनो प्रारूप में प्रभावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड–19 के पहले की मांग एवं पूर्ति की तुलना में मंदी के दौर में पहुंच गयी औा बाजार मं मांग एवं पूर्ति में अंसतुलन हो गया । जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार में कटौती की जाने लगी। जिसके कारण औद्योगिक इकरानामा बंद हो गयी और लोग बेरोजगार हो गये, उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। मजदूर वर्ग अपने–घरों की तरफ पलायन करने लगें। देश में चारो तरफ सड़को पर लोग समूह में रूप में जाते हुए दिखाई दिये। वहीं दूसरी तरफ जरूरी सेवाओं के अलावा सभी संवाओं की आपूर्ति भी लम्बें समय तक स्थिर रहीं। आम आदमी को जीवन जीना दुर्भर हो गया।

कोविड–19 की वजह से उत्पन्न वित्तिय अनुपलब्धता के कारण सरकार ने अपना खर्च कुल 22 फीसदी की कटौती कर दी। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड–19 में बेरोजगारी, गरीबी, मंहगाई, असमानता के एक भयावह च्रक में फस गयी। सरकार का टेक्स रेवेन्यू 10 फीसदी की दर से गिरने की ओर अग्रसर हो गया। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ये सुधार 1 फीसदी तक ही सिमट कर रह गया।

बाजार में मांग की कमी ने बेरोजगारी की समस्या को और बल दिया है, नवबंर महीने में औसत बेरोजगारी दर 6.5 फीसदी के ऊपर रही है, औसत दर पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है, मंहगाई दर नवबंर महीने में 6.93 फीसदी रही है, वहीं खाद्य महंगाई दर 9.43 फीसदी रही है।

अरूणसिंह मुख्य अर्थशास्त्री डन और ब्रैडस्ट्रीट इंडिया ने कहां "चीन के अलावा अन्य वैश्विक विनिर्माण केन्द्रों में भी तालाबन्दी की जा रही है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक विकास में कमजोरी बढ़ सकती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि पर सिंह ने कहा "भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए, भारत की जीडीपी वृद्धि हमारे वित्तिय वर्ष 20 के लिए 5 प्रतिशत के पहले के अनुमान से आगे मध्यम रहने की उम्मीद है और वित्तीय 21 के लिए विकास अत्यधिक अनिश्चित रहेगें।

रिर्पोट के अनुसार, वाणिज्यिक गतिविधियों और लोगों की सभाओं पर तालाबंदी और प्रतिबंध से वैश्विक और घरेलू विकास को जोरदार रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

मूल्य परिदृश्य पर, मांग और उत्पादन गतिविधियों में मंदी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में तेज गिरावट और अन्य प्रमुख वस्तुओं जैसे ऊर्जा, आधार धातुओं और उर्वरकों में कीमत घट जाएगी, मुद्रास्फीति पर दबाव बढाने की उम्मीद है।

अकंटाड़ विश्लेषण के अनुसार कमोडिटी से भरपुर निर्यातक देशों को अगले दो वर्षों में विदेशों से निवेश में $2.3 ट्रिलियन की गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया गया। अंकटाड़ की रिर्पोट के अनुसार जिस गति से कोविड–19 से विकासशील देशों को आर्थिक झटका लगा है, वह काफी ड्रामेटिक हैं। अंकटाड़ के महासचिव मुखिसा ने कहा, "सदमें से आर्थिक गिरावट जारी है और भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चींजे बहुत खराब होगी।

रिर्पोट और कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार विश्व में कई देशों की अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के कारण कॉफी विपरीत प्रभाव पडने की आंशका है।

निवेशकों के बाजारों से बाहर निकलने के कारण शेयर बाजार सूचकांक में लगातार गिरावट आई है। लोग बड़ी राशि को अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र यथा सरकारी बॉण्ड़ में निवेश कर रहे है। जिससे कीमतों में तेजी तथा उत्पादकता में कमी आयी है।

निष्कर्ष

- 32 करोड़ विद्यार्थियों की पढाई प्रभावित हुई, अक्टूबर मे अंत तक स्कूलों के बंद रखने से।
- 12 करोड़ बच्चे मिड डे मिल (एमडीएम) योजना में शामिल थे उनकों इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
- केवल 2.7 प्रतिशत परिवरों को ही कोविड–19 में अपनी मुलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम्प्यूटर तक पहुॅच बना पाये।
- 40 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्रों में रमिकों को अपनी आमदनी से नुकसान हुआ।
- भारत में अरबपतियों की सम्पत्तियों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2009 के बाद 422.9 अरब डॉलर के ऑकडे से 90 प्रतिशत अधिक थी।
- केवल 6 प्रतिशत सबसे परिवारों ही स्वास्थ्य साधनों तक अपनी पहुँच बना पाये।
- 84 प्रतिशत परिवारों को अप्रेल 2020 में अपनी आमदनी से नुकसान हुआ।

उपाय

- भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं वित्तिय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- अब आवश्यकता है छोटे स्तर पर नए रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने के लिए सरकार नई नीति के साथ काम करें, बाजार में रोजगार के जरिये आय का सृजन करने पर ध्यान दिया जा सकता है। रोजगार सृजन के परिणाम स्वरूप बाजार में पुनः मांग लौटेगी तथा मांग एवं पूर्ति में अस्थिरता दूर होगी जिसमें निवेश बढेगा तथा रोजगार एवं आय का सृजन का कार्य प्रगति की ओर बढेगा।
- हालांकि सब देशों में वैक्सीन आने के बाद धारे–धारे सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हो जायेगा। लेकिन फिर भी यह समझना आवश्यक है कि पिछले कुछ महिनों में क्या हुआ ताकि हम चुनौतियों का समाधान खोज सके। सरकार को इस बात को ध्यान मे रखना होगा। इस और विकास की गति को बढाने देना होगा।
- कोविड–19 की वजह से उत्पन्न हुई वित्तीय अनु उपलब्धलता ने भी सरकार को अपने खर्चो में 22 फीसदी तक की कटौती करनी पडी। ऐसे में सरकारों को वित्तीय निवेशों में वृद्धि करने एवं सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढाने पर ध्यान दिया जायें।
- भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत करने के लिए आयात–निर्यात में संतुलन स्थापित करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. इण्डिया टुडे ऑक्सफोर्ड इनइक्लालिटी रिर्पोट फरवरी 2021
2. राजस्थान पत्रिका फरवरी संस्करण
3. 2019–20 में कैसी रही भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत ?
4. नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार रिर्पोट
5. कोविड–19 भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव होगा?
6. योजना
7. कुरूक्षेत्र
8. "लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं करपा रही अर्थव्यवस्था जाने" जनसत्ता जुलाई 2020
9. भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक
10. कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियाँ ORF मूल से 10 मई 2020
11. नवभारत टाइम्स जुलाई 2020
12. द हिन्दू
13. अहमद जुबैर (1 मई 2020) कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ
14. भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्मी नारायण नाथूरामका
15. राजस्थान मे आर्थिक पर्यावरण डॉ. बी. पी. गुप्ता

❖◆❖